RAJYA SABHA

Friday, the 6th August, 1993/15th Sravana, 1915 Saka

The House met at eleven of the clock, THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 161... *(Interruptions)*.

SHRI VIZOL: Madam, I want to read a statement made by a Minister of Manipur. It is of national importance... *(Interruptions)*.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is it? ... *(Interruptions)*. If it is related to Question No. 161, I will allow; otherwise, no.

SHRI VIZOL: It is very important. I think the House should know about it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please take your seat... *(Interruptions)*. Please don't disturb... *(Interruptions)*.

SHRI VIZOL: I am reading it now.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Nothing will go on record... *(Interruptions)*. Don't behave like this... *(Interruptions)*. I won't permit it... *(Interruptions)*. This is not the time... *(Interruptions)*. In the Question Hour, one doesn't do these things... *(Interruptions)*...

आपने घड़ी देखी है, क्या बजा है ? अभी 11 बजे हैं, 12 नहीं बजे हैं ।

श्री एस० एस० अहलुवालिया : महोदया, वह घड़ी नहीं देख रहे हैं, वह आपको देख रहे हैं । आपको देखकर 12 बजे का समय उन्हें याद आ गया ।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा

*161. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 16 जुलाई, 1991 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 142 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव का उत्तर भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के प्रस्तावित मामले के संबंध में भारत सरकार ने मई, 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार से यह पूछा था कि क्या राज्य सरकार परिवर्तन के बाद भी वर्तमान स्तर पर योजनेत्तर व्यय देना जारी रखने, केन्द्रीय विश्वविद्यालय की प्रशासन व प्रबंध पद्धति अपनाने, संबद्ध कालेजों को किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपते हुए विश्वविद्यालय के एकल (यूनीटरी) स्वरूप को अपनाने, और भविष्य में विस्तार के लिए राज्य सरकार से निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाने को सहमत है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुछ शर्तें रखते हुए उक्त प्रश्नों का उत्तर दिया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्यय के वर्तमान स्तर का जायजा लेने का अनुरोध किया गया है ताकि अंतिम निर्णय लेते समय सरकार को इस परिवर्तन के संबंध में वित्तीय वचनबद्धता की सही जानकारी मिल सके । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों को सहयोजित करने का अनुरोध किया गया है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय उपसभापति जी, 23 सितम्बर, 1887 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना अधिनियम संख्या-18 के अनुसार हुई थी और 15 नवम्बर, 1887 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रथम दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ था । उपसभापति महोदया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को "ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट" भी कहा जाता है । इस सदन के भूतपूर्व सभापति व देश के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति डॉ० शंकर दयाल शर्मा, देश के दो भूतपूर्व प्रधान मंत्री जोकि इस समय लोकसभा के सदस्य हैं — श्री चन्द्रशेखर जी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और माननीय श्री अर्जुन सिंह जी — ये सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और अभी इसी सदन के सदस्य श्री टी० एन० चतुर्वेदी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं । इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं तथा वहां की कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं सभी मानव संसाधन विकास मंत्री जी से विद्या दान के उपलक्ष में गुरू दक्षिणा भी चाहते हैं ।

मेरा प्रश्न यह है कि मई, 1991 में उत्तर प्रदेश के सरकार ने जो पत्र लिखा था तो भारत सरकार की ओर से कुछ शर्तों के साथ उत्तर दिया गया था इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के बारे में, तो वह शर्तें क्या रखी हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में सहमति व्यक्त की है या नहीं ?

* Not recorded.

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रिस्पांस दिया है, उसमें पहली बात यह है कि वह नॉन-प्लान एक्सपेंडीचर को बर्दास्त करने के लिए आफ्टर कनवर्सन तैयार हैं और करेंट लोकल एक्सपेंडीचर के आधार पर । दूसरे यह कि जो 4 कांस्टीट्यूएंट कालेजेज हैं, वह तो यूनिवर्सिटी के साथ रहेंगे, लेकिन जो अन्य 10 कॉलेजेज हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उनको और किसी विश्वविद्यालय से एफिलिएट किया जाए । तीसरा, यह कि राज्य सरकार इस बात पर विचार करेगी कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए जमीन फ्री आफ कॉस्ट आगे देने की पहल करे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : उपसभापति जी, मैं यह भी जानना चाहता हूं, अभी तक पूर्व में केन्द्र सरकार की नीति रही है कि जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, उनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, लेकिन अभी हाल में बहुत अच्छा कदम उठाया गया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में डा० भीमराव आम्बेडकर जो विश्वविद्यालय था वह राज्य स्तर का था, लेकिन उसको केन्द्रीय स्तर का विश्वविद्यालय कर दिया, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, हम लोग भी उसकी मांग कर रहे थे, तो उसी नीति को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि सिद्धांत रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करने के संबंध में केन्द्र सरकार सहमति देती है या नहीं ?

श्री अर्जुन सिंह : यहां तक प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रश्न है, ऐसा तो कोई निर्णय, आदरणीया, नहीं हुआ है । डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिणित करने के पीछे दोनों सदनों से कई माननीय सदस्यों ने आग्रह किया था और साथ ही साथ डा० आम्बेडकर शताब्दी के अवसर पर यह सब की राय से उचित माना गया कि उस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर दिया जाए । इसलिए वह कोई प्रिसिडेंट नहीं है अन्य विषय पर निर्णय लेने के लिए । यहां तक हर स्टेट में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्तर का विश्वविद्यालय हो, इसके बारे में सी०ए०बी० कमेटी की एक सब-कमेटी बनाई गई थी, जो डा० कृष्णदास सुनहरी, मिनिस्टर गुजरात के नेतृत्व में बनी थी । उन्होंने एक जो रिपोर्ट दी है, उसमें एक पालिसी गाइडलाइन नई यूनिवर्सिटी खोलने की, केन्द्रीय यूनिवर्सिटी खोलने की है । साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि बजाय नई सब यूनिवर्सिटी एकदम खोलने के हर प्रदेश में जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो उसके स्तर को ऊंचा किया जाए और इस तरह स्तर को ऊंचा करके इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जो एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में होती है । यह उनकी कमेटी का सुझाव है और उस पर विचार हो रहा है ।

श्री रंजन प्रसाद यादव : मैडम, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय, मानव संसाधन विकास विभाग से जानना चाहूंगा कि बिहार सरकार पिछले कई वर्षों से पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए अनुशंसा और सिफारिश करती रही है और केन्द्र सरकार ने आश्वासन भी दिया था, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मंशा केन्द्र सरकार रखती है या नहीं ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया, मैंने जैसा अभी कहा कि कोई नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान नहीं है, लेकिन डा० सुनहरी की रिपोर्ट के आधार पर उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए हम हर प्रदेश में, बिहार भी उसमें आता है, सारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन वह सीमित दायरे में होगा, नए विश्वविद्यालय के रूप में नहीं होगा । यह स्पष्ट होना चाहिए । . . . **(व्यवधान)**. . .

श्री ईशादत्त यादव : मैडम, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है, मई, 1991 में राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था और राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अपना उत्तर भेज दिया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पार्ट "ए" है, कि इसमें विलंब क्यों किया जा रहा है ? दो वर्ष हो गया है । फिर इसके आगे, जब उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर मिल गया, आपने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखा, इसके बाद इस तरह की ढीली कार्यवाही इसके बारे में क्यों चल रही है ? कब तक आप इसको पूरा कर लेंगे ? और, इसको शीघ्रता करने में क्या कठिनाई है ? "जी" पार्ट है, मैडम, कि क्या दूसरे विश्वविद्यालय, जिनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी गई है. . . **(व्यवधान)**. . .

उपसभापति : अभी उसका जवाब उन्होंने दे दिया, इसलिए वह सवाल मत पूछिए । . . . **(व्यवधान)**. . . पहले का जवाब दे दिया ।

श्री ईशादत्त यादव : नहीं, नहीं, इसका नहीं दिया है । . . . **(व्यवधान)**. . .

उपसभापति : वह दे देंगे ।

श्री ईशादत्त यादव : जो विश्वविद्यालय राज्य सरकार के थे, जिनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, उनके लिए भी क्या यह शर्तें लगाई गई या नहीं लगाई गई ? अगर नहीं लगाई गई तो प्रयाग विश्वविद्यालय के लिए क्यों लगाई जा रही हैं ?

श्री अर्जुन सिंह : मैंने स्पष्ट किया कि जहां तक डाक्टर भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय का सवाल था, किन परिस्थितियों में उसे केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया, वह कोई पूर्व उदाहरण किसी दूसरे प्रकरण के लिए नहीं होगा । जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रश्न है, आपने जो सवाल पूछा है, उसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यू०जी०सी० ने जो कमेटी बनाई है, जो उस पर विचार कर रही है यू०पी० गवर्नमेंट की शर्तों के बारे में, वह अगले दो महिने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी और फिर उस पर विचार किया जाएगा ।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आदरणीया उपसभापति महोदया, जहां तक प्रयाग विश्वविद्यालय का प्रश्न है, यह एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है — चौथी यूनिवर्सिटी जब कि देश में यूनिवर्सिटीयां कायम हुई थीं । आप चाहे उसको विज्ञान के क्षेत्र में देखें — मेघनाथ साहा, बीरबल साहनी, एन०पी०एल० के संस्थापक डा० कृष्णन्, सर शफ़ाअत अहमद खां और उसी प्रकार दूसरे सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी देखें या इतिहास के क्षेत्र की ओर देखें — डा० ईश्वरी प्रसाद, डा० तारा चन्द, डा० राम प्रसाद त्रिपाठी इत्यादि, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का दुर्भाग्य यह है कि यह पहले सैंट्रल यूनिवर्सिटी थी लेकिन उसके बाद इसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया । इलाहाबाद से सीधे गवर्नमेंट के लखनऊ जाने के बाद वहां का और ह्रास होने लगा और अब यह हालत है कि 1887 में जब इसकी सेन्टेनरी हो रही थी, उसके लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री के पास आए थे डा० यू० एन० सिंह, जो उस समय वहां के वाइस चांसलर थे और एक-आध हम लोग भी साथ गए थे । तत्कालीन प्रधान मंत्री महोदया ने यह आश्वासन दिया था मगर दुर्भाग्य से वह परिस्थितियां बदल गई और वह संभव नहीं हुआ । मेरा केवल निवेदन यह है, मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है, जो सैंट्रल यूनिवर्सिटी थी और जहां पर कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के विद्यार्थी, उसका आगर क्षेत्रफल आप देखें और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब वहां के खुद एलम्नि रहे हैं और वह जानते हैं, सब क्षेत्रों के — राजनीतिक, सामाजिक, सबके विकास में उसका योगदान रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो उसका सैंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेट्स था उसको शीघ्र, बिना किसी और उदाहरण को लिए हुए, क्यों नहीं तुरन्त उसके संबंध में कार्यवाई की जाती ?

मेरे सवाल का दूसरा भाग यह है कि यह जो कमेटी यू०जी०सी० ने काएम की है . . . .

उपसभापति : सवाल कम समय में पूछिए तो जवाब भी कम समय में आएगा ।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : महोदया, मैं समाप्त कर रहा हूं । क्या उस कमेटी के साथ मालवीय जी या एक-आध और लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है ? क्योंकि कमेटियां टालू मिक्सर पिलाने के लिए ही बहुत सी और खासकर के यूनिवर्सिटी के पास, यू०जी०सी० कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसी स्थिति में टालू मिक्सर देने का ही इरादा है या उसके पीछे कोई सिन्सियरिटी है । अतः मैं यह जानना चाहूंगा, बिना किसी और उदाहरण को दिए हुए, अपनी मेरिट के ऊपर उसको क्यों नहीं रेस्टोर किया जाता है ?

श्री अर्जुन सिंह : आदरणीया जहां तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रश्न और उसका जो स्थान है देश के शैक्षणिक जगत में उसके बारे में तो कोई दो राय हो नहीं सकती और हम जैसे साधारण लोग भी वहां पढ़े हैं, हम अपने लिए यह बहुत गौरव की बात समझते हैं । . . . **(व्यवधान)** . . .

श्री शंकर दयाल सिंह : हम आपको साधारण नहीं समझते । आपने कहा है कि हम जैसे साधारण, हम आपको साधारण नहीं समझते, विशेष समझते हैं ।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shankar Dayalji, please do not interrupt. I am very sorry that even during the Question Hour Members get up without any recognition by the Chair. Please don't do it. I won't like it.

श्री अर्जुन सिंह : जहां तक इस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का स्तर देने का सवाल है, यह प्रश्न अभी बंद तो नहीं किया गया । जो वहां स्टेट गवर्नमेंट से आए हैं, उनके आधार पर यू०जी०सी० एग्ज़ामिन कर रही है । रिपोर्ट आने दीजिए । उस वक्त हम आप सब लोगों से परामर्श करेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है । उस प्रश्न को खत्म नहीं किया गया है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं ।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभापति महोदया, सबसे पहले मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने बगैर सीधे संदर्भ के डाक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय का दो बार यहां जिक्र किया । उनकी सरकार को तो हम पहले ही बधाई दे चुके हैं । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सत्र में आश्वस्त किया गया था कि चालू सत्र में डाक्टर भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय संबंधी एक विधेयक लाया जाएगा । लेकिन सारी कार्यवलि का अवलोकन करने से ऐसा आभास होता है कि इस सत्र में उस विधेयक के सम्बन्ध में कोई किसी तरह का इंडिकेशन नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं, क्या-अ . . . **(व्यवधान)** . . .

उपसभापति : भाग-अ नहीं, आप एक ही सवाल पूछिए ।

I have got so many names. I have to give chance to other Members also.

श्री संघ प्रिय गौतम : एक ही पूछ रहा हूं । तो इस सत्र में यह विधेयक क्यों नहीं लाया गया ? यदि लाया जाएगा तो कब और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने विधेयक बनाया था और अब तक जो उसके मुंतजिम थे, क्या उनसे भी सलाह मशवरा करके विचार-विमर्श किया जाएगा ?

श्री अर्जुन सिंह : यह बिल्कुल सही है कि जितना शीघ्र हम इस विधेयक को लाना चाहते थे, वह नहीं आया । उसका कारण यही है जो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि वहां ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ऐक्ट बना हुआ है और उसके तहत काम शुरू है । हमें उसको इंटीग्रेट करना होगा । उसमें यू०पी० गवर्नमेंट का पूरा-पूरा परामर्श और उनको भी कुछ कदम उठाने होंगे । इसलिए इसमें थोड़ा विलम्ब हुआ है । आप आश्वस्त रहें, उस मामले में हमारी तरफ से कोई ढील नहीं दी गई है । हम पूरी कोशिश में हैं कि जितना जल्द हो सके हम उस विधेयक को पार्लियामेंट के सामने लाएं ।

उपसभापति : अगर आगे के सवाल सिर्फ जो असली

क्वेश्चन है, उससे संबंधित है तो मैं एलाउ करूंगी, वरना नहीं करूंगी। मोहम्मद खलीलुर रहमान। पूरे हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटीज के बारे में सवाल एलाउ नहीं करूंगी।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : मोहतरमा डिप्टी चेयरमैन साहिबा, यूनिवर्सिटी स्टेट की ज़ानिब से है, जो इंतहाई कामयाबी के साथ चलाई जा रही है और कुछ यूनिवर्सिटी जो हैं, वह सेंटर की ज़ानिब से है। मगर अभी जैसा कि मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा है कि उनकी जो कमेटी है उस कमेटी की सिफारिश के बिनाह पर किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी अगर अच्छी तरह से चल रही है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जा सकता है। मैं ऑनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह पूछना चाहता हूं कि बजाय इसके कि स्टेट की जो यूनिवर्सिटी इंतहाई कामयाबी के साथ चल रही है उसको स्टेट की ज़ानिब से चलने दीजिए। अगर किसी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप वहां नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलिए। क्या ऐसा मुमकिन है?

شری محمد خلیل الرحمٰن: محترمہ ڈپٹی چیئرمین صاحبہ۔ یونیورسٹی اسٹیٹ کی جانب سے ہیں جو انتہائی کامیابی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے۔ وہ سنٹر کی جانب سے ہیں۔ مگر ابھی جیسا کہ منسٹر صاحب نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ انکی جو کمیٹی ہے اس کمیٹی کی سفارش کے بنا پر کسی اسٹیٹ کی یونیورسٹی اگر اچھی طرح سے چل رہی ہے تو اس کو سنٹرل یونیورسٹی بنایا جا سکتا ہے۔ میں آنریبل منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اسٹیٹ کی جو یونیورسٹی انتہائی کامیابی کے ساتھ چل رہی ہے اس کو اسٹیٹ کی جانب سے چلنے دیجئے اگر کسی اسٹیٹ میں سنٹرل یونیورسٹی نہیں ہے تو آپ وہاں نئی سنٹرل یونیورسٹی کھولئے کیا ایسا ممکن ہے۔

THE DEPUTY CHAIRMAN : Thank you.

श्री अर्जुन सिंह : शायद सम्मानित सदस्य ने मेरे उत्तर को सही संदर्भ में नहीं समझा। मेरा तात्पर्य यही था कि जो वह पूछ रहे हैं। जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले से है वहां तो प्रश्न उठता नहीं है। लेकिन जिन राज्यों में नहीं है वहां किसी यूनिवर्सिटी के स्तर को ऊंचा करने के लिए जो वहां व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षण के लिए जरूरी है, उनको ऊंचा करने के लिए है और नई यूनिवर्सिटी खोलने के बजाय यह कदम उठाना है।

श्री मोहम्मद खलीलुर रहमान : तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है?

شری محمد خلیل الرحمٰن: تو کیا اتر پردیش میں کوئی سنٹرل یونیورسٹی نہیں ہے۔

उपसभापति : श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे, इसी सवाल से सम्बन्धित हो तो पूछें, सारी यूनिवर्सिटीज का नहीं पूछें।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे : नहीं-नहीं, प्रैदम, इसी सवाल से संबंधित है। मंत्री महोदय ने यह बताया है कि जो उनको कमेटी की रिपोर्ट आ गई है तो हर स्टेट में वह यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं? मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूं कि नौर्थ ईस्ट में जहां लोगों को आने-जाने के लिए सुविधा नहीं है तथा आज जो बारिश हो रही है तो इस कारण भी लोगों का वहां कोई सम्पर्क नहीं रहा है, तो ऐसी जगह यूनिवर्सिटी मिजोरम में एनाउंस की है, नागालैंड में भी हो सकती है? यह नौर्थ ईस्ट की जो सेवेन सिस्टर्स हैं वहां के सवाल बहुत कठिन हैं। तो क्या हम उन्हें शिक्षा से वंचित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार विचार कर रही है कि ज्यादा प्रायोरिटी देकर मिजोरम या नागालैंड में यूनिवर्सिटी जल्द खोलना चाहती है?

श्री अर्जुन सिंह : नागालैंड में यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला हो चुका है, एनाउंस हो चुका है और वहां वाईस चांसलर जल्दी ही नियुक्त होने वाले हैं। आसाम में दो यूनिवर्सिटी इसी संदर्भ में खोली गई हैं। जो और मांगें हैं, उन पर भी विचार हो रहा है।

SHRI MD. SALIM : Question No. 162. Where is the Minister, Madam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : I am here, Madam ...

THE DEPUTY CHAIRMAN : That is a written answer. You say that it is laid on the Table of

*[ ] Tranlation in Arabic Script.

?[ ] Transliteration in Arabic Script.

the House.

SHRI P. K. THUNGON : It is very small, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN : It is not laid? Read it.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ : It is not laid, Madam...

उपसभापति : बोलिए ।

SHRI P. K. THUNGON : It is very small. It is of three sentences only.

Measures to Control Floods in North Eastern Region

*162. SHRI MD. SALIM : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether effective measures have been taken by Government to control flood in North Eastern Region; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON) : (a) and (b) Effective measures taken have provided protection to an area of about 19 lakh hectares out of the total 43.41 lakh hectares of flood prone area in North-Eastern Region. These mainly consist of construction of embankments, drainage channels and anti-erosion works. In addition, 20 flood forecasting stations are working to provide timely warnings to the local people for mitigation of flood losses.

श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, इसका बहुत महत्व समझा जाता है और इसको सरकार भी महत्व देती है । आसाम या पूरे नार्थ-ईस्ट क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप हर साल है, स्टीम की तरह है और सरकार ये कह रही है कि हमने 20 फोरकास्टिंग स्टेशंस बना दिए हैं । जब बाढ़ आएगी, तो लोग भागना शुरू कर दें । आजादी के 46 साल बाद हमारी वॉटर रिसोर्स मिनिस्ट्री नार्थ-ईस्ट, पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, इनके बारे में, उसको फिक्र नहीं है । मंत्री महोदय यहां ऐजसेंट हैं । जब उन्होंने ब्रह्मपुत्र बोर्ड बनाया है तो उसकी मीटिंग बरसों नहीं होती । जो ब्रह्मपुत्र के मास्टर प्लान बनाए हुए हैं, वह मंत्री महोदय के पास दिए हुए हैं लेकिन आज तक सरकार ने अपनी राय नहीं बताई कि वह क्या करेगी ।

महोदया, अभी अप्रैल महीने में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की मीटिंग थी चार साल बाद, वह ऐडजार्न हो गई क्योंकि महत्वपूर्ण अफसरान वहां पर मौजूद नहीं थे । वैसे तो बोर्ड में कहने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, प्राईम-मिनिस्टर, नार्थ-ईस्ट के चीफ-मिनिस्टर्स सब हैं लेकिन बोर्ड में 1987 से कोई चेयरमैन नहीं है, कोई वाईस-चेयरमैन नहीं है, 1989 से, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है, 1991 से और सेक्रेटरी नहीं है । 1987 से तो इस ब्रह्मपुत्र बोर्ड को एक साईनबोर्ड बनाकर रख दिया गया है जिसकी इतनी अहमियत थी क्योंकि ये इतना बैकवर्ड रीजन है । इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि नार्थ-ईस्ट में बहुत बैकवर्डनेस है । वहां पर जो फ्लड का मैग्नीट्यूड है, हर साल जो बरबादी होती है चाहे वह प्रापर्टी हो, चाहे वह जान-माल हो लेकिन सरकार कोई ऐसे कदम नहीं उठाती जिससे कि वहां कोई परमानेंट अरेंजमेंट किया जा सके, परमानेंट सौल्यूशन किया जा सके ।

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या समयबद्ध तरीके से वॉटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ब्रह्मपुत्र बोर्ड को कारगर बनाएगी और उनके जो खाली पद हैं, उनको भरेगी ? ब्रह्मपुत्र बोर्ड जिस मंशा से बनाया गया था, जिस मकसद से बनाया गया था कि नार्थ-ईस्ट में परमानेंट सौल्यूशन हो सके और खासकर ब्रह्मपुत्र वैली में बाढ़ की रोकथाम करने के लिए परमानेंट सौल्यूशन हो सके । तो वाकई ब्रह्मपुत्र बोर्ड कोई काम कर सके, इसके लिए आप उनके जो रिक्त पद हैं उनको कब तक भरेंगे ?

شری محمد سلیم : میڈم۔ اس کا بہت مہتو سمجھا جاتا ہے اور اس کو سرکار بھی مہتو دیتی ہے۔ آسام یا پورے نارتھ ایسٹ اکثیتر میں باڑھ کا پرکوپ ہر سال ہے روٹین کی طرح ہے اور سرکار سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ۲۰ فورکاسٹنگ اسٹیشن بنا دیئے ہیں۔ جب باڑھ آئے گی تو لوگ بھاگنے شروع کر دیں۔ آزادی کے ۴۶ سال بعد ہماری واٹر رسورس منسٹری نارتھ ایسٹ۔ پورو آتر جو راجیہ ہیں ان کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہے۔ منسٹری مہودے یہاں اسینٹے ہیں جب انہوں نے